भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं0 228

02 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

सस्ते किराया आवास परिसर

228. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाईयू) के अंतर्गत सस्ते किराया आवास परिसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;
(ख) यदि हां, तो अभी तक निर्मित सस्ते किराया आवासों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-यू के अंतर्गत सस्ते किराया आवास परिसर को विकास के लिए संस्वीकृत / प्रयुक्त कुल राशि संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या क्या है;
(ङ) निर्माण के लिए ऐसी नव प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने आवास परिसरों के किराए की गणना के लिए कोई सूत्र विकसित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री)

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्य स्थल के पास सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी)

को मिशन अवधि के दौरान दिनांक 31.07.2020 को आरंभ किया गया है। यह योजना निम्नानुसार दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है:

(I) मॉडल-1: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित सरकार द्वारा वित्तपोषित मौजूदा खाली आवासों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएचसी में परिवर्तित करके उपयोग करना।

(II) मॉडल-2: सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा उनकी खाली पड़ी भूमि पर एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव।

इसके अतिरिक्त, एआरएचसी योजना का विवरण http://arhc.mohua.gov.in/filesUpload/Operational-Guidelines-of-ARHCs.pdf पर उपलब्ध है।

योजना के मॉडल-1 के तहत, अब तक, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 5,648 खाली आवासों को एआरएचसी में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में 7,413 खाली आवासों हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) किए गए हैं।

मॉडल-2 के तहत, 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1,39,471 इकाइयों के निर्माण के लिए सार्वजनिक/निजी संस्थाओं से 73 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तत्पश्चात्, मंत्रालय द्वारा 7 राज्यों में 82,273 नई एआरएचसी इकाइयों के निर्माण के 13 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। अब तक, मंत्रालय द्वारा नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके 82,273 नई एआरएचसी इकाइयों के निर्माण के लिए 174 करोड़ रुपये का प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में 30,001 नई एआरएचसी इकाइयों का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। एआरएचसी की प्रगति का राज्य/शहर-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(च): एआरएचसी के परिचालन दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि एआरएचसी का प्रारंभिक किफायती किराया स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर तय किया जाएगा। इसके बाद, किराए में द्विवार्षिक रूप से 8% की वृद्धि की जाएगी, जो 5 साल की अवधि में कुल मिलाकर 20% के अधिकतम वित्तपोषण के अधीन होगा और यह संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगी। संपूर्ण रियायत अवधि अर्थात 25 वर्षों के दौरान समान तंत्र का पालन किया जाएगा।

*****

02.02.2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं0 228 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क. योजना के मॉडल-1 के तहत लाभार्थियों के लिए एआरएचसी में परिवर्तित किए गए सरकार द्वारा वित्तपोषित मौजूदा खाली आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर	एआरएचसी में परिवर्तित खाली आवासों की सं0	लाभार्थियों द्वारा कब्ज़ा किए गए आवास
1	चंडीगढ़	चंडीगढ़	2,195	2,195
2	गुजरात	सूरत	393	393
3	गुजरात	अहमदाबाद	1,376	1,376
4	गुजरात	राजकोट	698	-
5	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	480	-
6	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	336	336
7	उत्तराखंड	लालकुआं	100	100
8	उत्तराखंड	देहरादून	70	70
कुल			**5,648**	**4,470**

ख. योजना के मॉडल-2 के तहत सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत एआरएचसी इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	शहर/राज्य का नाम	संस्था का नाम	प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी	कुल इकाइयां
1.	श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु	एसपीआर सिटी एस्टेट प्रा. लिमिटेड	मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम	18,112
2.	श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड	मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम	3,969
3.	होसुर, तमिलनाडु	टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्रा. लिमिटेड	प्रिकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम	13,500
4.	चेन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम	मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम	18,720
5.	चेन्नई, तमिलनाडु	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम	1,040
6.	रायपुर, छत्तीसगढ़	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम	2,222

7.	कामपुर नगर, असम	गुवाहाटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम	2,222
8.	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम	1,112
9.	सूरत, गुजरात	मित्सुमी हाउसिंग प्रा. लिमिटेड	लाइट गॉज स्टील फ़्रेमड़ स्ट्रक्चर	453
10.	चेन्नई, तमिलनाडु	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड	एल्युमिनियम फॉर्म वर्क	5,045
11.	निजामपेट, तेलंगाना	सिवनी इंफ्रा प्रा. लिमिटेड	मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम	14,490
12.	काकीनाड, आंध्र प्रदेश	कोस्टल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम	736
13.	विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	कोस्टल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम	652
कुल				**82,273**

******